भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.02.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 115 का उत्तर

सरकारी कंपनियों के साथ साझेदारी

115. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने मौजूदा रेल नेटवर्क को अन्य सरकारी कंपनियों के साथ साझेदारी/साझा करने की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्ययोजना तैयार की गई है; और
(ग) उक्त साझेदारी से रेलवे को कितना लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): जी हां। रेल मंत्रालय ने इच्छुक हितधारकों की सहभागिता से पत्तन, खदानों, उद्योग समूह आदि तक रेल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए भागीदारी नीति-2012 तैयार की है। कई कोयला कंपनियां, पत्तन, उद्योग समूह आदि इस नीति के तहत भागीदारी करने हेतु आगे आए हैं। राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/सरकारी कंपनियां/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी रेल मंत्रालय की इस भागीदारी नीति के तहत नई लाइनों/आमान परिवर्तन परियोजना के विकास के लिए हितधारकों और निवेशकों के रूप में भाग ले रहे हैं। ऐसी सभी परियोजनाओं में निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेलगाड़ी परिचालन रेलवे द्वारा ही किया जा रहा है। भागीदारी नीति के तहत शुरू की गई परियोजनाएं रेलवे में काफी सफल पाई गई हैं जो सभी हितधारकों जैसे पत्तनों, कोयला कंपनियों, उद्योग समूह और सहायक राज्य सरकारों खास तौर पर कई पत्तनों और उद्योग समूह के लिए अंतिम मील रेल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए लाभकारी सिद्ध हुई हैं। अभी तक, ऐसी 14 परियोजनाएं पूरी की गई हैं और 10 परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

****